



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

### गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्या:-2023 / 203

दर्ज तिथि:-03 / 07 / 2023

1. दीपाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार निवासी मगासर गोलिया जेतमाल, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल जरिये सरपंच गोलिया जेतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
2. उतमाराम पुत्र ठाकराराम
3. डुगराराम पुत्र मगाराम
4. देवाराम पुत्र राउराम
5. भूरीदेवी पत्नी राउराम
6. मूलीदेवी पत्नी सुखाराम
7. गंगादेवी पत्नी मालाराम
8. श्रीमान तहसीलदार नोखड़ा।

.....असल प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता

अपीलार्थी:- श्री रामजीवण विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-75

राज. भू-राजस्व अधिनियम-1956

### :-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतः विवरण इस प्रकार से है:-
  - कि हाल आराजी खसरा 572 / 5.0909 है0 मौजा गोलिया जेतमाल तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी मे अपीलार्थी का 1 / 6 हिस्सा निहित था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31.09 बीघा में से अपीलार्थी का 1 / 8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 02 को बेचान किया गया। परंतु



उक्त बेचान का नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 गलत रूप से दर्ज किया गया। अपीलार्थी के खसरा संख्या 572 रकबा 31.09 बीघा में 1/6 हिस्से का हक निहित था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2019 द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31.09 बीघा में से केवल 1/8 हिस्से अर्थात् 3.931 बीघा भूमि का बेचान किया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 572 में अपीलार्थी की आराजी शेष है। परंतु बेचान दिनांक 27.06.2019 का नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 दर्ज कर खसरा संख्या 572 में अपीलार्थी का संपूर्ण हिस्सा प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड से अपीलार्थी का नाम ही कलमजन कर दिया।

- इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 गलत दर्ज किया गया है। खसरा संख्या 572 में अभी भी अपीलार्थी की आराजी निहित है। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए उक्त आराजी में अपीलार्थी का शेष हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त प्रत्यर्थी विधिवत तामील उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैंने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में अपील के निस्तारण से पूर्व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के उपशमन के लिये प्रार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निर्णयन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा दिनांक 20.04.2019 को नामांतरकरण संख्या 94 पारित किया गया। जिसमें अपीलार्थी की सम्पूर्ण आराजी का बैचान बताया जाकर नामांतरकरण गलत रूप से पारित किया गया। परंतु उक्त बैचान नामांतरकरण के पश्चात् भी अपीलार्थी की आराजी शेष है तथा उक्त शेष आराजी पर अपीलार्थी काबिज होकर काशत करता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर केसीसी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करनी चाही। तब अपीलार्थी को सर्वप्रथम उक्त आराजी में अपना नाम नहीं होने का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को नामांतरकरण संख्या 94 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। उक्त नामांतरकरण के माध्यम से अपीलार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा बैचान किया हुआ होना ज्ञात हुआ। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने से अपीलार्थी का उक्त नामांतरकरण के संबंध में पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। अंत में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को नामांतरकरण संख्या 94 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.06.2023 को प्राप्त होने पर अन्दर म्याद उक्त अपील प्रस्तुत कर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा दिनांक 20.04.2019 को उक्त नामांतरकरण संख्या 94 पारित किया गया है। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा लगभग 1503 दिवस की लम्बी अवधि के पश्चात् दिनांक 03.07.2023 को उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने के कारण अपीलार्थी को उक्त नामांतरकरण के संबंध में ज्ञान नहीं हुआ। परंतु अपीलार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काशत करता आ रहा है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर केसीसी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर सर्वप्रथम अपीलार्थी को उक्त आराजी में अपना नाम नहीं होने ज्ञात हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को नामांतरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त कर 13 दिवस के भीतर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलार्थी के बैचान के पश्चात् शेष आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होने एवं अपीलार्थी को अपने विरुद्ध हुई नामांतरकरण कार्यवाही का ज्ञान होने पर निश्चित अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से अपीलार्थी अपने विरुद्ध हुई कार्यवाही के प्रति संवेदनशील प्रतीत होता है।
5. साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी उक्त शेष आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काशत करता आ रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के काशतकार राजस्व इन्द्राज के दुरुस्त रहने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं एवं राजस्व कार्मिकों से नियमित रूप से अपने राजस्व इन्द्राज की जानकारी नहीं लेते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ-साथ अपनी आराजी पर आकस्मिक कोई कार्य उत्पन्न होने पर ही राजस्व कार्मिकों से अपने आराजी के राजस्व इन्द्राज की जानकारी लेते हैं। साथ ही ग्रामीण पृष्ठभूमि के काशतकार ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड की समझ व तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण अपने स्तर पर अपने राजस्व इन्द्राज के लिये राजस्व कार्मिकों पर ही निर्भर रहते हैं। अतः प्रकरण में अपीलार्थी के ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने से भी अपीलार्थी को बैचान के नामांतरकरण से दर्ज किये गये राजस्व इन्द्राज का ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक प्रतीत होता है।
6. इसी प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने बैचान दस्तावेज के अमलदरामद के नामांतरकरण संख्या 94 के विरुद्ध परिसीमा के तहत अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण में निहित प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार को अकारथ अन्याय हुआ है तथा परिसीमा अवधि के कारण पक्षकार के न्याय के रास्ते बंद हो चुके हैं, उन प्रकरणों में न्यायालय देरी के उपशमन के मामलों में प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में व्यापक देरी का उपशमन करने हेतु अपने विवेक एवं अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में व्यापक देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के दरवाजे खोलने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी को बिना सुने राजस्व रिकॉर्ड के अपीलार्थी की समस्त आराजी प्रत्यर्थी के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड पर सम्पूर्ण हिस्सा कलमजन कर दिया। निःसन्देह इस प्रकार कार्यकरण से

अपीलार्थी के पक्ष में अकारथ अन्याय होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के हस्तगत मामले में व्यापक देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के दरवाजे खोलने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझता है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन किया जाता है।

7. अब प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन होने के पश्चात् प्रकरण नामांतरकरण दर्ज करने की प्रक्रिया पर विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत होता है। सर्वप्रथम प्रकरण में नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 के नियम-121 के उपनियम-04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया व प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

### 121. General instructions.-

*(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance. the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.*

*(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberan Fallan Raqba Fallan Manzor Hai" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.*

8. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 के नियम-121 के उपनियम-04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैं:-

प्रक्रिया	प्रावधान
1	<i>The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.</i>
2	<i>The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,</i>
3	<i>the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,</i>
4	<i>what opportunity was given to him to present,</i>
5	<i>who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.</i>
6	<i>but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,</i>
7	<i>the facts which they deposed and the grounds of the order.</i>
8	<i>The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.</i>

9. प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 के नियम-121 के उपनियम-04 तथा 05 के अनुसार ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा द्वारा निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उक्त प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विश्लेषण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया	विश्लेषण
<i>The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.</i>	नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है
<i>The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,</i>	नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों के विवरण तथा उनकी उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। <u>इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।</u>
<i>the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,</i>	नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। <u>इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।</u>
<i>what opportunity was given to him to present,</i>	नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों

	को प्रदान किये गये सुनवाई/उपस्थिति के अवसरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।
<i>who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.</i>	नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों की उपस्थिति की परिस्थिति में पक्षकारों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।
<i>but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,</i>	नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों/व्यक्तियों से फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच/जिरह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।
<i>the facts which they deposed and the grounds of the order.</i>	नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय के तथ्यों/आधारों के बारे में कोई उल्लेख/जिक नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।
<i>The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.</i>	नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के ऑपरेटिव भाग के संक्षिप्त विवरण के बारे में कोई उल्लेख/जिक नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।

10. इस प्रकार प्रकरण में नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नामांतकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा को फैसल करते समय ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 के नियम-121 के उपनियम-04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

11. अब प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन होने के पश्चात् प्रकरण का गुणावगुण पर विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में तहसीलदार नौखड़ा व गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक/रीडर/2025/105 दिनांक 21.01.2025 द्वारा प्रेषित की गई। साथ ही तहसीलदार नौखड़ा द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक

रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/2025/13 दिनांक 09.01.2025 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त उभय रिपोर्ट से निम्न तथ्य सामने आते हैं-

- ❖ बेचान दस्तावेज 15.03.2019 में प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्सा निहित था। इस प्रकार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.2417 बीघा भूमि हिस्से में आती है।
- ❖ तत्समय की जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था।
- ❖ बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि का बेचान करने का उल्लेख किया गया है।
- ❖ बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि के बेचान पर रकबा 3.931 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है।
- ❖ बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि के बेचान के पश्चात नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 द्वारा अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर क्रेता का नाम दर्ज कर दिया गया।

12. इस प्रकार के प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बेचान दस्तावेज 15.03.2019 में प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्सा निहित था। परंतु तत्समय की जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्से के स्थान पर अपीलार्थी का केवल 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। इस प्रकार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.2417 बीघा भूमि हिस्से में आती है। साथ ही बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि का बेचान करने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात 3.931 बीघा भूमि के बेचान पर रकबा 3.931 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है।

13. इस प्रकार स्पष्ट है कि बेचान दिनांक 15.03.2019 के समय की जमाबंदी में अपीलार्थी का हिस्सा 1/8 गलत दर्ज था। असल में बेचान दिनांक 15.03.2019 के समय की जमाबंदी में अपीलार्थी का हिस्सा 1/6 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार बेचान दिनांक 15.03.2019 के समय की जमाबंदी में अपीलार्थी का हिस्सा 1/8 गलत दर्ज हिस्से के अनुसार बेचान पंजीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी दीपाराम का खसरा संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.2417 बीघा भूमि हिस्से में आती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बेचान दिनांक 15.03.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा

संख्या 572 रकबा 31-09 बीघा में 1/8 हिस्सा अर्थात् 3.931 बीघा भूमि के बेचान पर रकबा 3.931 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है। इस प्रकार खसरा संख्या 572 में अपीलार्थी के हक हकूक की खातेदारी आराजी 5.2417 बीघा में से बेचान दिनांक 15.03.2019 के द्वारा 3.931 बीघा भूमि का बेचान के पश्चात खसरा संख्या 572 में शेष आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त आधारों पर उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*अपीलार्थी की अपील बाबत नामांतरण संख्या 94 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल की दिनांक-05.11.2019 की कार्यवाही निरस्त की जाती है। मौजा मगासर तहसील नौखड़ा के खसरा संख्या 572 में अपीलार्थी के हक हकूक की खातेदारी आराजी 5.2417 बीघा में से बेचान दिनांक 15.03.2019 के द्वारा 3.931 बीघा भूमि का बेचान के पश्चात खसरा संख्या 572 में शेष आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
गुड़ामालानी (बाड़मेर)